



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-27112024-258950
CG-MH-E-27112024-258950

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 938]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2024/ अग्रहायण 6, 1946

No. 938]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2024/ AGRAHAYANA 6, 1946

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

अधिसूचना

मुंबई, 27 नवम्बर, 2024

सं.सीओ:ईआरडी:पीडी:798:2024—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र संख्या 4/2/2015-IR, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 के अनुसरण में की गई या करने से छोड़ी गई बातों को छोड़कर, 1 नवम्बर, 2017 से इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि तक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा.

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे.

2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (जिसे आगे उक्त विनियम कहा जाएगा) के विनियम 3 में, -

(1) खंड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(एफ़) चिकित्सा सुविधाओं के प्रयोजनों और छुट्टी किराया रियायत के प्रयोजनों के लिए "परिवार" से तात्पर्य, अधिकारी के पति या पत्नी, पूर्णतः आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चों और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित) पूर्णतः आश्रित शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग भाई या बहन जो चालीस प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले हों, विधवा पुत्रियां और आश्रित तलाकशुदा/पति से अलग हुई पुत्रियां, अविवाहित या तलाकशुदा अथवा पति से अलग हुई या परित्यक्त या विधवा बहन तथा अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित माता-पिता, से है।

व्याख्या -

- (i) अभिव्यक्ति "पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्य" से तात्पर्य परिवार के ऐसे सदस्य से है जिसकी आय अधिकतम ₹12,000/- प्रति माह है। यदि माता-पिता में से किसी एक की आय ₹12,000/- प्रति माह से अधिक है अथवा माता-पिता दोनों की कुल आय ₹12,000/- प्रति माह से अधिक है, तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माना जाएगा।
- (ii) एक विवाहित महिला अधिकारी अपने नैसर्गिक माता-पिता या सास-ससुर को परिवार की परिभाषा में शामिल कर सकती है, लेकिन दोनों को नहीं, बशर्ते कि माता-पिता या सास-ससुर पूरी तरह से उस पर निर्भर हों।

नोट: (1) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना के उद्देश्य से, सभी अधिकारियों, अर्थात् पुरुष या महिला, के लिए आश्रित माता-पिता या सास-ससुर में से किन्हीं दो को कवर किया जाएगा। अधिकारी के पास आश्रितों में से किसी एक या दोनों को प्रतिस्थापित करने का विकल्प होगा।

नोट: (2) किसी अधिकारी के शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को आयु या वैवाहिक स्थिति के निरपेक्ष आश्रितों के रूप में परिभाषित किया जाएगा, आय मानदंड के शर्तार्थिन;"

(2) उक्त विनियमों के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्रबंध निदेशक" का तात्पर्य बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है।

3. उक्त विनियमनों के विनियम 4 में, -

(i) उप-विनियम (6) में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (7), (8) और (9) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(7) 1 नवंबर, 2017 से प्रत्येक वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होगा:

(ए) शीर्ष कार्यपालक वर्ग

वेतनमान VII = ₹ 116120 – 3220/4 – 129000

वेतनमान VI = ₹ 104240 - 2970/4 - 116120

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग

वेतनमान V = ₹ 89890 – 2500/2 – 94890 – 2730/2 - 100350

वेतनमान IV = ₹ 76010 – 2220/4 – 84890– 2500/2 – 89890

(सी) मध्य प्रबंधन वर्ग

वेतनमान III = ₹ 63840 -1990/5– 73790 - 2220/2 - 78230

वेतनमान II = ₹ 48170 – 1740/1 - 49910 -1990/10 - 69810

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन वर्ग

वेतनमान I = ₹ 36000 -1490/7- 46430-1740/2-49910-1990/7-63840.

व्याख्या.- प्रत्येक अधिकारी जो 31 अक्टूबर, 2017 को लागू वेतनमान द्वारा शासित होता है, उसे 1 नवंबर, 2017 को चरण-दर-चरण आधार पर इस उप-विनियमन में निर्धारित वेतनमान में फिट किया जाएगा, अर्थात्, संबंधित वेतनमान में पहले चरण से आगे के अनुरूप चरणों में और वेतन वृद्धि सामान्य रूप

से प्रतिवार्षिक तिथि को होगी, बशर्ते जहां अन्यथा प्रावधान किया गया हो।

(8) 31 मार्च, 2020 से शीर्ष कार्यपालक वर्ग के वेतनमान- VIII के लिए निर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे: -

वेतनमान VIII = रु 166350-4400/4 - 183950

(9) उप-विनियम (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) और (8) में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक को प्रत्येक समय इन सभी वर्गों में सेवारत अधिकारी रखने की आवश्यकता है।

(iii) उप-विनियम (9) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:-

(10) (ए) 1 नवम्बर, 2012 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ता का भुगतान किया जाएगा: -

वेतनमान I – III - मूल वेतन का 7.75% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV – V - मूल वेतन का 10% और उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI – VII - मूल वेतन का 11% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता।

(बी) 1 नवम्बर, 2017 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ता का भुगतान किया जाएगा:

वेतनमान I – III - मूल वेतन का 16.40% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV – V - मूल वेतन का 19% और उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI – VIII - मूल वेतन का 20% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता:

बशर्ते कि वेतनमान VIII का अधिकारी 31 मार्च, 2020 से विशेष भत्ते के लिए पात्र होगा।

टिप्पणी: उप-विनियम 10 के खंड (क) और (बी) में निर्दिष्ट विशेष भत्ते तथा उस पर लागू महंगाई भत्ते को नई पेंशन योजना, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी सहित पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के लिए नहीं गिना जाएगा।

4. उक्त विनियमनों के विनियम 5 में, -

(i) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(1) विनियमन 4 के उप-विनियम (7) और (8) के प्रावधानों के अधीन, 1 नवम्बर, 2017 से वेतन वृद्धि निम्नलिखित के अधीन प्रदान की जाएगी, यथा: -

(ए) विनियम 4 के उप-विनियम (7) और (8) में निर्धारित वेतनमान में निर्दिष्ट वेतन-वृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन, वार्षिक आधार पर उपार्जित होगी और जिस माह में देय है, उस माह के पहले दिन प्रदान की जाएगी;

(बी) अपने-अपने वेतनमानों में अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष बाद, वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को अगले उच्चतर वेतनमान में गतिरोध वेतन-वृद्धि के साथ वेतन-वृद्धि प्रदान की जाएगी, जैसा कि नीचे खंड (ग) में निर्दिष्ट है, बशर्ते कि वे दक्षता मानदंड को पार कर लें;

(सी) कनिष्ठ प्रबंधन वर्ग वेतनमान I के अधिकारी, जो उच्चतर वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद खंड (बी) के अनुसार मध्यम प्रबंधन वर्ग वेतनमान II के वेतनमान में चले गए हैं, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए पांच गतिरोध वेतन-वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहले दो वेतन-वृद्धियां 1990/- रुपये प्रत्येक और अगले तीन वेतन-वृद्धियां 2220/- रुपये प्रत्येक होंगी:

बशर्ते कि अधिकारी चौथी गतिरोध वेतन वृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवम्बर, 2017 को, जो भी बाद में हो, पांचवीं गतिरोध वेतन-वृद्धि के लिए पात्र होगा;

(डी) मध्य प्रबंधन वर्ग वेतनमान II के अधिकारी, जो खंड (बी) के अनुसार उच्चतर वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद मध्य प्रबंधन वर्ग के वेतनमान III में चले गए हैं, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए 2220/- रुपये की दर से पांच गतिरोध वेतन-वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि अधिकारी चौथी गतिरोध वेतन वृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवम्बर, 2017 को, जो भी बाद में हो, पांचवीं गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा;

- (ई) मूल रूप से मध्य प्रबंधन वर्ग वेतनमान III के अधिकारी अर्थात्, जो कि मध्य प्रबंधन वर्ग वेतनमान III में भर्ती हुए हैं या पदोन्नत हुए हैं, वे छः गतिरोध वेतन-वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से 2220/- रुपये की पहली चार गतिरोध वेतन-वृद्धि प्रत्येक दो वर्ष की पूर्ण की गई सेवा के लिए अधिकतम तक पहुंचने के बाद दी जाएगी और 2500/- रुपये की अगली दो गतिरोध वेतन वृद्धि प्रत्येक दो वर्ष की पूर्ण की गई सेवा के लिए चौथी गतिरोध वेतन वृद्धि प्राप्त करने के बाद दी जाएगी:

बशर्ते कि छठी गतिरोध वेतन वृद्धि पांचवीं वेतन वृद्धि के जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2017 जो भी बाद में हो, को जारी की जाएगी;

- (एफ) वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग वेतनमान IV के अधिकारी, वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए दो गतिरोध वेतन-वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहली गतिरोध वेतन-वृद्धि 2500/- रुपये की होगी और दूसरी गतिरोध वेतन वृद्धि 2730/- रुपये की होगी:

बशर्ते कि अधिकारी प्रथम गतिरोध वेतन-वृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवम्बर, 2017 को, जो भी बाद में हो, द्वितीय गतिरोध-वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा;

- (जी) 1 नवंबर, 2017 को बैंक में अपनी सेवा के दौरान वेतनमान I से वेतनमान IV तक के अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई गतिरोध वेतन-वृद्धि को उनके अधिकतम तक पहुंचने की तिथि से तीन वर्ष की आवधिकता से दो वर्ष की आवधिकता में पुनः समायोजित किया जाएगा और अधिकारी संशोधित आवधिकता के अनुसार 1 नवंबर, 2017 से गतिरोध वेतन-वृद्धि के लिए अनुमानित रूप से पात्र होंगे जो कि सेवानिवृत्ति लाभ के लिए पात्र होंगे. हालांकि, गतिरोध वेतन-वृद्धि की ऐसी संशोधित और पुनः समायोजित आवधिकता के कारण मौद्रिक लाभ 1 नवंबर, 2020 या पात्रता की वास्तविक तिथि, जो भी बाद में हो, से देय होगा ;

- (एच) वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग वेतनमान V में अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर 2020 को, जो भी बाद में हो, 2970/- रुपये की एक गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते यह वेतन-वृद्धि उस अधिकारी को नहीं दी जाएगी जिसने पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया हो.

स्पष्टीकरण.- इस उप-विनियम के अंतर्गत अगले उच्चतर वेतनमान में ऐसी वेतन वृद्धि प्रदान करना पदोन्नति नहीं माना जाएगा और अधिकारियों के विशेषाधिकार, परिलब्धियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व उनके मूल पद के अनुसार जारी रहेंगी."

- (ii) उप-विनियम (2) में, स्पष्टीकरण में, खंड (जी) के पश्चात् और नोट से पूर्व, निम्नलिखित खंड सम्मिलित किया जाएगा, यथा:-

“ (एच) 1 नवंबर, 2017 से, अन्य बातों के समान होने पर, व्यावसायिक आहर्ता वेतन की मात्रा नीचे दी गई तालिका के अनुसार संशोधित होगी : -

तालिका

जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भाग I परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है	(i) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद से रु. 1020 प्रतिमाह.
जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिया हो	(i) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद से रु. 1020 प्रति माह. (ii) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के दो वर्ष बाद से रु. 2550 रुपये प्रति माह:

बशर्ते कि वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद भारतीय बैंकर्स संस्थान के जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (दोनों में से कोई एक या दोनों भाग) योग्यता प्राप्त करने वाले अधिकारी को ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त प्रदान की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की बाद की किस्त, ऐसी व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त के जारी होने की तारीख के आधार पर जारी होगी;

(iii) उप-विनियम (3) में, -

(ए) खंड (एफ) में, तालिका के पश्चात्, नोट (i) से (vi) का लोप किया जाएगा;

(बी) खंड (जी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

1 नवंबर, 2017 को और से (जी), अन्य बातें समान होने पर, मकान किराया भत्ते के साथ नियत वैयक्तिक वेतन निम्नलिखित दरों पर होगा और पूरी सेवा अवधि के लिए स्थिर रहेगा: -

तालिका

क्रम सं.	वेतन वृद्धि घटक (रु.)	1 नवंबर, 2017 को वेतन वृद्धि घटकों पर महंगाई भत्ता (रु.)	देय कुल निश्चित व्यक्तिगत वेतन जहां बैंक द्वारा आवास की सुविधा उपलब्ध है (रु.)
1.	(1)	(2)	(3)
2.	1990	53	2043
3.	2220	59	2279
4.	2500	66	2566
5.	2730	73	2803
6.	2970	79	3049
7.	3220	86	3306

टिप्पणी:

- (i) इस उप-विनियमन के खंड (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ) और (जी) में तालिका के कॉलम (3) के अंतर्गत निर्दिष्ट निश्चित व्यक्तिगत भत्ता या निश्चित व्यक्तिगत वेतन उन अधिकारियों को देय होगा, जिन्हें बैंक आवास उपलब्ध कराया गया है.
- (ii) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन, उक्त तालिका के कॉलम (1) और (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुल राशि होगी तथा संबंधित अधिकारी द्वारा विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5), (6) और (7) में विनिर्दिष्ट प्रासंगिक वेतनमान की अंतिम वेतन वृद्धि अर्जित करने पर प्राप्त किया गया मकान किराया भत्ता होगा.
- (iii) केवल वे अधिकारी जो 1 नवम्बर, 1993 को या उससे पहले बैंक की सेवा में रहे हों, वे अपने अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के एक वर्ष बाद निश्चित वैयक्तिक वेतन के लिए पात्र होंगे.
- (iv) 1 नवम्बर, 1999 को तथा उस तिथि से, निश्चित वैयक्तिक वेतन जारी किए जाने के कारण उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (सी) के अनुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन जारी किए जाने की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

बशर्ते जहां व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई किस्त, जो पूर्ववर्ती उपबंधों के कारण एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाई गई है और 1 नवंबर, 1999 को या उसके पश्चात् जारी होने वाली है, वह अधिकारी को इसी तारीख से जारी की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, 1 नवंबर, 2000 को जारी की जाएगी.

- (v) निश्चित व्यक्तिगत भत्ता या निश्चित व्यक्तिगत वेतन का वेतन वृद्धि घटक सेवानिवृत्ति लाभ के लिए रैंक किया जाएगा.
- (vi) कोई अधिकारी, जिसने उपर्युक्त खंड (ए) के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि अर्जित की है, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात्, उपर्युक्त खंड (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) में उल्लिखित निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन की मात्रा प्राप्त करेगा:
- (एच) 31 मार्च, 2020 को तथा उस तिथि से, अन्य बातें समान होने पर, शीर्ष कार्यपालक वर्ग के वेतनमान-VIII में मुख्य महाप्रबंधक के पद के लिए मकान किराया भत्ते के साथ-साथ निश्चित व्यक्तिगत वेतन नीचे दी गई तालिका में दी गई दरों पर होगा और यह पूरी सेवा अवधि के लिए स्थिर रहेगा:

तालिका

वेतन वृद्धि घटक (रु.)	वृद्धि घटकों पर महंगाई भत्ता (रु.)	जहां बैंक की सुविधा उपलब्ध है वहां देय कुल निश्चित व्यक्तिगत वेतन (रु.)
(1)	(2)	(3)
4400	117	4517"

5. उक्त विनियमन के विनियम 20 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) में, "चेयरमैन एवं" शब्दों को हटा दिया जाएगा.

6. उक्त विनियमनों के विनियम 21 में, -

- (ए) उप-विनियम (6) में, स्पष्टीकरण के खंड (बी) में, कोष्ठक, शब्द और अक्षर "(एफ) और (जी)" के स्थान पर, कोष्ठक, शब्द और अक्षर "(एफ), (जी) और (एच)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (बी) उप-विनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) दिनांक 1 नवम्बर, 2017 से अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के तिमाही औसत में 6352 अंकों से अधिक प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि या कमी के लिए वेतन का 0.07% महंगाई भत्ता देय होगा.;

7. उक्त विनियमन के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1) दिनांक 1 नवंबर, 2017 से -

- (ए) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, वहां उसके वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के या आवास के लिए मानक किराये के 0.50 प्रतिशत के बराबर राशि, जो भी कम हो, उससे वसूल किया जाएगा;
- (बी) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, वहां वह निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होगा, अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं.	कार्यस्थल	मकान किराया भत्ता
1.	(2)	(3)
2.	समूह ए में प्रमुख "ए" श्रेणी के शहर और परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 9.0%
3.	समूह बी में क्षेत्र I के अन्य स्थान एवं परियोजना क्षेत्र केंद्र तथा गोवा राज्य	वेतन का 8.0%

4.	अन्य स्थान	वेतन का 7.0%
----	------------	--------------

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, उसके द्वारा आवासीय आवास के लिए भुगतान किया गया वास्तविक किराया होगा जो उस वेतनमान के प्रथम चरण में वेतन के 0.50 प्रतिशत से अधिक होगा जिसमें वह है, तथा मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150 प्रतिशत, जो उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित दरों के अनुसार देय होगा.

टिप्पणी: अधिकारियों के उनके स्वामित्व आवास की लागत से जुड़े मकान किराया भत्ते के दावे भी अब तक की तरह मकान किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित रहेंगे.”.

8. उक्त विनियमनों के विनियम 23 में,

(ए) उप-विनियम (i), (ii), (iii), (iv) और (v) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(i) दिनांक 1 नवम्बर, 2017 से, यदि कोई अधिकारी नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में उल्लिखित स्थान पर सेवारत है, तो उस स्थान के सापेक्ष स्तंभ (2) में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा:

तालिका

क्रम सं.	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	क्षेत्र 1 और उससे ऊपर तथा गोवा राज्य में स्थित स्थान	रु. 1400/- प्रति माह
2.	पांच लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान तथा राज्य की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पुडुचेरी और पोर्ट ब्लेयर	रु. 1150/- प्रति माह

- (ii) दिनांक 1 नवम्बर, 2017 से विशेष क्षेत्र भत्ते की दरें इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी.
- (iii) दिनांक 1 नवंबर, 2017 से, यदि कोई अधिकारी समूह ए या समूह बी में आने वाले परियोजना क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्र में सेवा कर रहा है, तो वह समूह ए या समूह बी के रूप में क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार क्रमशः 600 रुपये प्रति माह या 525 रुपये प्रति माह की दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र होगा.
- (iv) दिनांक 1 नवंबर, 2020 से, यदि किसी अधिकारी को शैक्षणिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसके एक या एक से अधिक बच्चे पूर्व स्थान पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वह सभी बच्चों के लिए नए स्थान पर रिपोर्टिंग तिथि से उस शैक्षणिक वर्ष के अंत तक, रु. 1650/- प्रति माह की दर से मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ते के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि यदि सभी बच्चे पूर्व स्थान पर पढ़ाई बंद कर देते हैं तो ऐसा भत्ता बंद हो जाएगा.
- (v) दिनांक 1 नवंबर, 2020 से, यदि किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह उस पद से जुड़ी परिलब्धियों को प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया है, या वह अपने वेतन के अतिरिक्त, वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता, जो अधिकतम 6000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है और ऐसे अन्य भत्ते जो उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने पर मिलते, प्राप्त कर सकता है:

बशर्ते कि यदि उसे ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है जो उसी स्थान पर स्थित है जहां वह प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले तैनात था, तो उसे अपने वेतन के चार प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा जो अधिकतम 3000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है:

आगे यह भी प्रावधान है कि बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने वेतन के 4 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए पात्र होगा, जो अधिकतम 3000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है.”

(वी) उप-विनियम (viii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(viii) दिनांक 1 नवम्बर, 2017 से, यदि किसी दिन के कार्य घंटों को न्यूनतम दो घंटों के अंतराल पर विभाजित किया जाता है, तो अधिकारी 300 रुपए प्रति माह की दर से विभाजित ड्यूटी भत्ते के लिए पात्र होगा.”

(सी) उप-विनियम (x) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(x) दिनांक 1 नवंबर, 2017 से कोई भी अधिकारी नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्र और ईंधन भत्ते के लिए पात्र होगा, अर्थात्:-

तालिका

क्र. सं.	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	1000 मीटर या उससे अधिक लेकिन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान और मर्कारा टाउन	वेतन का 2%, अधिकतम रु.1125/- प्रति माह
2.	1500 मीटर या उससे अधिक किन्तु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 2.5%, अधिकतम 1500 रुपये प्रति माह
3.	3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 5%, अधिकतम 3000/- रुपये प्रति माह

(डी) उप-विनियम (x) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(xi) दिनांक 1 नवंबर, 2017 से अधिकारी 600 रुपए प्रतिमाह के शिक्षण भत्ते तथा उस पर महंगाई भत्ते के लिए पात्र होंगे.

(xii) दिनांक 1 नवंबर, 2017 से, वे अधिकारी जो नगर प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में तैनात हैं, वे 700/- रुपये प्रति माह के निश्चित भत्ते के लिए पात्र होंगे. इस निश्चित भत्ते की गणना महंगाई भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभों, अर्थात् नई पेंशन योजना सहित पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेज्युटी के भुगतान के लिए नहीं की जाएगी.

(xiii) वित्तीय वर्ष 2020-21 से, सभी अधिकारियों को परिचालन लाभ या शुद्ध लाभ के आधार पर सामान्य वेतन के अतिरिक्त वार्षिक रूप से कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा. नीचे उल्लिखित कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन मैट्रिक्स बैंक के वार्षिक कार्यनिष्पादन के आधार पर देय राशि (वेतन के दिनों की संख्या = मूल वेतन + महंगाई भत्ता) तय करेगा:

क्रम संख्या	परिचालन लाभ में वर्ष दर वर्ष वृद्धि	दिनों की संख्या जिसके लिए वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का भुगतान किया जाएगा
(1)	(2)	(3)
1.	< 5%	शून्य
2.	5% से 10%	5 दिन
3.	> 10% से 15%	10 दिन*
4.	> 15%	15 दिन*

*तीसरा और चौथा स्लैब तभी देय होगा जब बैंक को निवल लाभ हो. यदि बैंक के परिचालन लाभ में 5 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि हुई है, लेकिन निवल लाभ नहीं हुआ है, तो न्यूनतम 5 दिन का दूसरा स्लैब देय होगा.”

9. उक्त विनियमनों के विनियम 24 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) दिनांक 1 नवंबर, 2017 से कोई अधिकारी स्वयं तथा परिवार हेतु चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए नीचे दी गई तालिका के अनुसार पात्र होगा, बशर्ते कि दावा की गई के लिए अधिकारी ने स्वयं ऐसा व्यय करने का प्रमाण पत्र दिया हो, जो उसके खाते के विवरण द्वारा समर्थित हो, अर्थात्: -

तालिका

क्रम संख्या	वर्ग	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन संवर्ग	रु.10300/- प्रति वर्ष या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो
2.	वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यपालक संवर्ग	रु.12300/- प्रति वर्ष या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो

नोट: (i) किसी अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता को संचित करने की अनुमति दी जा सकती है, जो किसी भी समय ऊपर प्रदान की गई अधिकतम राशि से तीन गुना से अधिक नहीं होगी, या

(ii) वर्ष 2017 के लिए चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो माह अर्थात् नवम्बर, 2017 और दिसम्बर, 2017 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी”.

10. उक्त विनियमन के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(2) उप-विनियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, बैंक किसी अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए अधिकारी को दिनांक 1 नवंबर, 2017 से उसके वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के या आवास के लिए मानक किराया के 0.50 प्रतिशत के बराबर राशि, जो भी कम हो, का भुगतान करना होगा:

बशर्ते कि जहां अधिकारी को ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया गया हो, वहां उसके वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि बैंक द्वारा उससे वसूल की जाएगी:

आगे यह भी प्रावधान है कि जहां ऐसी आवासीय सुविधा बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, वहां बिजली, पानी, गैस और सफाई के लिए व्यय अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा.”.

11. उक्त विनियमनों के विनियम 32 में, उप-विनियम (2) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: -

"स्पष्टीकरण- इस विनियमन के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि-

(ए) वर्ष 2017 या किसी भी बाद के वर्षों में नहीं ली गई आकस्मिक छुट्टी अगले पांच वर्षों में समाप्त हो जाएगी:

(बी) दिनांक 1 नवंबर, 2020 से अधिकारी द्वारा अप्रयुक्त आकस्मिक अवकाश चिकित्सा आधार पर अनुमत किया जाएगा और एक साथ चार दिनों तक की ऐसी अप्रयुक्त आकस्मिक छुट्टी की अवधि के लिए कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है.”.

12. उक्त विनियमनों के विनियम 33 में-

(ए) उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) दिनांक 1 जून, 2015 से अधिकतम दो सौ सत्तर दिन तक विशेषाधिकार अवकाश संचित किया जा सकेगा, सिवाय उस स्थिति के जहां अवकाश के लिए आवेदन किया गया हो और उसे अस्वीकार कर दिया गया हो:

बशर्ते कि विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम दो सौ चालीस दिन तक सीमित होगा:

आगे यह भी प्रावधान है कि कैलेंडर वर्ष, 2020 से, कोई अधिकारी अपनी पसंद के किसी भी त्यौहार के समय प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए पांच दिनों की दर से विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए भी पात्र होगा और कोई अधिकारी जो 1 जनवरी, 2020 को पचपन वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और उससे अधिक का है, तो वह एकमुश्त उपाय के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए सात दिनों की दर से विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए पात्र होगा."

(बी) उप-विनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(5) विशेषाधिकार अवकाश लेने की इच्छा रखने वाले अधिकारी को सामान्यतः अवकाश किराया रियायत के प्रयोजन को छोड़कर, ऐसे अवकाश लेने के अपने इरादे की कम से कम दस दिन पहले सूचना देनी होगी.

(सी) उप-विनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(6) बीमारी के कारण लिए गए विशेषाधिकार अवकाश की गणना, जब अधिकारी के पास कोई बीमारी अवकाश न हो, विशेषाधिकार अवकाश लेने के अवसर के रूप में नहीं की जाएगी."

13. उक्त विनियमनों के विनियम 34 में, उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(5) महिला अधिकारी अपने आठ वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर बीमारी अवकाश का लाभ ले सकती हैं."

14. उक्त विनियमन के विनियम 35 के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"35. अतिरिक्त बीमारी अवकाश - (1) दिनांक 1 जनवरी, 1989 से, जहां किसी अधिकारी ने चौबीस वर्ष की सेवा की है, वह चौबीस वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त बीमारी अवकाश के लिए पात्र होगा, किन्तु अतिरिक्त बीमारी अवकाश की अधिकतम सीमा तीन माह की होगी.

(2) दिनांक 1 नवंबर, 2017 से, जहां किसी अधिकारी ने तीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वह तीस वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह प्रति वर्ष दर से और अतिरिक्त बीमारी अवकाश के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि अतिरिक्त बीमारी अवकाश की अधिकतम सीमा तीन माह की होगी.

बशर्ते अधिकारी की सम्पूर्ण सेवा में बीमारी अवकाश की कुल संख्या सात सौ बीस दिन से अधिक नहीं होगी:

आगे यह भी प्रावधान है कि दिनांक 29 जून, 1999 को या उसके पश्चात् ली गई अतिरिक्त बीमारी छुट्टियों के मामले में, विनियम 34 के उप-विनियम (2) के अनुसार अतिरिक्त छुट्टी का संराशीकरण की अनुमति दिया जा सकेगा."

15. उक्त विनियमनों के विनियम 36 के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"36 मातृत्व अवकाश - (1) मातृत्व अवकाश की स्थिति में, -

(ए) कोई महिला कर्मचारी किसी एक अवसर पर छह माह से अनधिक अवधि के लिए तथा अपनी सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान बारह माह के लिए मूल वेतन पर मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी:

बशर्ते कि जुड़वा बच्चों के जन्म के मामले में मातृत्व अवकाश की अवधि आठ माह होगी:

आगे यह भी प्रावधान है कि मातृत्व अवकाश, आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ लिया जा सकेगा;

(बी) अकाल प्रसव, गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति या गर्भपात के मामले में, महिला कर्मचारी सक्षम चिकित्सक, जैसे कि योग्य स्त्री रोग विशेषज्ञ के चिकित्सा प्रमाण पत्र या सलाह के आधार पर छह सप्ताह तक का मातृत्व अवकाश ले सकती है। अकाल प्रसव या गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति या गर्भपात से जुड़ी चिकित्सा जटिलताओं से जुड़े विशेष या असाधारण मामलों में, सक्षम चिकित्सक (योग्य स्त्री रोग विशेषज्ञ) द्वारा सलाह दिए जाने पर, छह सप्ताह से अधिक मातृत्व अवकाश लिया जा सकता है, लेकिन सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह महीने की कुल सीमा के भीतर, किसी एक अवसर पर केवल छह महीने तक का मातृत्व अवकाश लिया जा सकता है;

(सी) बारह महीने की समग्र अवधि के भीतर, हिस्टेरेक्टॉमी के मामले में अधिकतम साठ दिनों तक की छुट्टी भी ली जा सकती है।

नोट: उन कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने बारह महीने का मातृत्व अवकाश लिया है और उसे समाप्त कर दिया है, उन्हें चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, इसके अतिरिक्त पंद्रह दिनों का अवकाश मंजूर किया जाएगा।

(डी) कोई निःसंतान महिला कर्मचारी, एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए सेवा के दौरान एक बार अधिकतम नौ महीने की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन छुट्टी ले सकती है, अर्थात: -

- (i) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए छुट्टी दी जाएगी;
- (ii) बच्चे को सही विधिक प्रक्रिया के जरिये गोद लेना चाहिए और ऐसा अवकाश मंजूर करने के लिए कर्मचारी को बैंक के समक्ष दत्तक-ग्रहण विलेख प्रस्तुत करना चाहिए;
- (iii) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी भी बच्चे को गोद लेने के लिए छुट्टी हेतु पात्र हैं;
- (iv) ऐसे मामलों में उन जैविक मां को भी अवकाश उपलब्ध होगा जहां बच्चे का जन्म सरोगेसी के जरिये हुआ है;
- (v) इस अवकाश का उपभोग सम्पूर्ण सेवा काल के दौरान बारह महीने की समग्र पात्रता के अंतर्गत किया जाएगा;

(ई) बारह माह की समग्र अवधि के भीतर, निम्नलिखित स्त्री रोग संबंधी बीमारियों या उपचार के कारण अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में भी अधिकतम तीस दिनों तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है:-

- (i.) असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव (एयूबी);
- (ii.) ऑवेरियन ट्यूमर;
- (iii.) ट्यूबेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी रिवर्सल;
- (iv.) प्रसवोत्तर अवसाद (पीपीडी);
- (v.) प्रसवोत्तर रक्तस्राव (पीपीएच);
- (vi.) तीव्र श्रोणि सूजन रोग (तीव्र पीआईडी);
- (vii.) डिसफंक्शन गर्भाशय रक्तस्राव; डिसफंक्शन (डीयूबी).

(2.) पितृत्व अवकाश के मामले में, 1 जून 2015 से प्रभावी, पुरुष कर्मचारी दो जीवित बच्चों हेतु उसकी पत्नी के प्रसव अवस्था के दौरान पंद्रह दिनों के लिए पितृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगे और यह अवकाश आकस्मिक अवकाश के अलावा किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ लिया जा सकता है:

बशर्ते कि छुट्टी बच्चे की डिलिवरी की तिथि से पंद्रह दिनों से पूर्व या छह महीने तक ली जा सकेगी:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि उपर्युक्तानुसार पितृत्व अवकाश दो जीवित बच्चों वाले पुरुष कर्मचारी को एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए दिया जा सकता है.”.

16. उक्त विनियमन के विनियम 37 के लिए, निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“37. असाधारण छुट्टी.- (1) कोई अधिकारी सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम चौबीस माह के लिए अवैतनिक अवकाश सहित असाधारण अवकाश हेतु पात्र होगा.

(2) कोई भी अधिकारी किसी एक अवसर पर तीन महीने से अधिक अवधि के लिए असाधारण अवकाश का लाभ उठा सकता है, तथा अत्यंत गंभीर चिकित्सा परिस्थितियों में वह किसी एक अवसर पर चार महीने तक का असाधारण अवकाश ले सकता है.

नोट: चिकित्सा आधार पर असाधारण अवकाश लेने के कारण कर्मचारी की वरिष्ठता में कोई कमी नहीं आएगी.”.

17. उक्त विनियमन में विनियमन 37ए के लिए, निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं, अर्थात्:-

“37ए. विशेष आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश.- (1) 1 नवंबर, 2020 से प्रभावी, कोई अधिकारी कर्मचारी ऐसे अवसरों पर विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा जब जिस शाखा में अधिकारी काम कर रहा है या जिस स्थान पर वह रह रहा है वह कर्फ्यू, दंगों, प्रतिषेधात्मक आदेश, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ आदि से प्रभावित है.

(2) 1 नवंबर, 2020 से प्रभावी, शारीरिक या अस्थि विकलांग अधिकारी चार दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होंगे.

(3) किसी अधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश तथा कोई भी विशेष अवकाश, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय किया जाए, प्रदान किया जा सकेगा.”

18. उक्त विनियमनों के विनियमन 41 में, उप-विनियम (4) में, खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ए) विराम भत्ता - 1 नवंबर, 2020 से प्रभावी, तालिका के कॉलम (1) में दिए गए वर्ग या वेतनमान में कोई अधिकारी कॉलम (2) में दी गई तदनुसार दरों पर 'प्रतिदिन' विराम भत्ते का हकदार होगा, अर्थात्: -

तालिका

क्र. सं.	अधिकारियों के वर्ग/वेतनमान	मेट्रो रु.	प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर रु.	क्षेत्र I रु.	अन्य स्थानों रु.
1.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	वेतनमान VI और उससे ऊपर के अधिकारी	2700	1950	1650	1425
3.	वेतनमान IV और V के अधिकारी	2250	1950	1650	1425
4.	वेतनमान I, II और III के अधिकारी	1950	1650	1425	1200:

बशर्ते कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम किन्तु चार घंटे से अधिक हो, वहां उपर्युक्त दरों की आधी दर पर विराम भत्ता देय होगा.

स्पष्टीकरण.- विराम भत्ते की गणना करने के प्रयोजन के लिए "प्रतिदिन" से चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसका पश्चातवर्ती भाग अभिप्रेत है, जिसकी गणना वायुयान यात्रा की स्थिति में, प्रस्थान के लिए रिपोर्ट के समय से और अन्य स्थितियों में प्रस्थान के निर्धारित समय से लेकर आगमन के वास्तविक समय तक की होगी और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, वहां "प्रतिदिन" से कम से कम आठ घंटे की अवधि अभिप्रेत है.”.

19. उक्त विनियमनों के विनियमन 42 में, उप-विनियम (3) के खंड (सी) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(3) (सी) 1 नवंबर, 2020 से प्रभावी, स्थानांतरित अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा आदि से जुड़े खर्चों के लिए निम्नवत सारणी के अनुसार एकमुश्त राशि के आहरण हेतु पात्र होंगे, अर्थात्: -

तालिका

क्रम सं.	वर्ग/वेतनमान	मात्रा
1.	(1)	(2)
2.	शीर्ष कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन (वेतनमान IV एवं ऊपर के अधिकारी)	Rs.30,000/-
3.	मध्यम प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन (वेतनमान III तक के अधिकारी)	Rs. 25,000/-".

20. उक्त विनियमनों के विनियमन 45 में, उप-विनियम (4) के नोट से पहले, निम्नलिखित प्रावधान डाले जाएंगे, अर्थात्:-

“बशर्ते कि परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना) के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों के संबंध में, बैंक 11 नवंबर, 2020 से वेतन और महंगाई भत्ते का चौदह प्रतिशत अंशदान करेगा :

बशर्ते कि नई पेंशन योजना के सेवा प्रदाता या निधि प्रबंधक के सेवा शुल्क का वहन वित्तीय वर्ष 2020-21 से बैंक द्वारा किया जाएगा.”.

21. उक्त विनियमनों की अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

“अनुसूची

(विनियम 23 का उप-विनियम (2) देखें)

1 नवंबर, 2017 से प्रभावी, एक अधिकारी नीचे दी गयी तालिका के अनुसार विशेष क्षेत्र भत्ता पाने का तब तक पात्र होगा, जब तक कि इसे पूर्ण रूप या आंशिक रूप से वापस नहीं ले लिया जाए या संशोधित न कर दिया जाए, अर्थात्: -

तालिका

विशेष क्षेत्र भत्ता

क्र. सं.	क्षेत्र	भत्ते (रु.)	
		रु. 36,001/- से कम वेतन	रु. 36,001/- से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मिजोरम (ए) चिम्पतुईपुई जिला और लुंगलेई जिले के लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से अधिक दूर के क्षेत्र.	4000	5200
	(बी) लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर पूरा लुंगलेई जिला.	3200	4200
	(सी) पूरा आइजोल जिला	2400	3000
2.	नागालैण्ड	3200	4200
3.	अंडमान व नीकोबार द्वीप समूह (ए) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, नीकोबार और नारकोंडम द्वीप	4000	5200

	(बी) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	3200	4200
4.	सिक्किम	4000	5200
5.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	4000	5200
6.	असम	640	800
7.	मेघालय	640	800
8.	त्रिपुरा (ए) त्रिपुरा के कठिन क्षेत्र	3200	4200
	(बी) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर पूरे त्रिपुरा राज्य में	2400	3000
9.	मणिपुर	2400	3000
10.	अरुणाचल प्रदेश (ए) अरुणाचल प्रदेश के कठिन क्षेत्र (बी) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर पूरे अरुणाचल प्रदेश में.	4000 3200	5200 4200
11.	जम्मू और कश्मीर (ए) कठुआ जिला: नियाबत बानी, लोही, मल्हार और मछोड़ी	4000	5200
	(बी) उधमपुर जिला: (i) भाग 2(बी) में शामिल के अलावा डुडु बसंतगढ़, लैंडर भमाग इलाका (ii) कंबन की ओर से गोयल तक के क्षेत्र और मोहरे तहसील में कियासी की ओर से अरनास तक का क्षेत्र.	4000 3200	5200 4200
	(सी) डोडा जिला: पैडर का इलाका और किशतवाड़ तहसील में और नियाबत नौगावं	4000	5200
	(डी) लेह जिला : जिले के सभी स्थान	4000	5200
	(ई) बारामुला जिला: (i) संपूर्ण गुरेज़-निराबात , तंगदार उप-मंडल और केरन इलाका (ii) मचेल	4000 3200	5200 4200
	(एफ) पूँछ और राजौरी जिला: पूँछ और राजौरी जिले के क्षेत्र (पूँछ और राजौरी कसबों तथा सुंदरबनी और दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर)	2400	3000
	(जी) वे क्षेत्र जो उपरोक्त (ए) से (एफ) में सम्मिलित नहीं हैं, किन्तु जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 कि.मी. की दूरी के भीतर हैं या ऐसे स्थान हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए सीमा भत्ते के लिए पात्र के रूप में घोषित किया जा सकता है।	2400	3000

12.	<p>हिमाचल प्रदेश</p> <p>(1) चम्बा जिला</p> <p>(ए) पांगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायत: बदगांव , बाजोल , देओल कुगती , नयागाम और टुंडा , गांव: ग्राम पंचायत जगत के घाटू , ग्राम पंचायत चौहाटा के कनारसी</p> <p>(बी) भरमौर तहसील, उपरोक्त (ए) में शामिल लिए गए पंचायतों और गांवों को छोड़कर.</p> <p>(सी) भटियट तहसील, चुराह तहसील, डलहौजी टाऊन (बनीखेत सहित) में झंडरू पंचायत तहसील ..</p>	<p>4000</p> <p>3200</p> <p>2400</p>	<p>5200</p> <p>4200</p> <p>3000</p>
	<p>(2) किन्नौर जिला:</p> <p>(i) असरंग , चितकुल और हांगोकुनो / चारंग पंचायत, 15/20 क्षेत्र जिसमें ऊपर निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर छोटा खम्बा , नाथपा और रूपी , पूह उप-मंडल, की ग्राम पंचायतें शामिल हैं.</p> <p>(ii) उपरोक्त (ए) में शामिल क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण जिला.</p>	<p>4000</p> <p>3200</p>	<p>5200</p> <p>4200</p>
	<p>कुल्लू जिला:</p> <p>(i) निरमंड तहसील में खरगा, कुशवार और सरगा ग्राम पंचायत का 15/20 क्षेत्र</p> <p>(ii) [बाहरी- सराज (निरमंड तहसील में जकात-खाना और बरो के गांवों को छोड़कर) और, बाहरी सराज क्षेत्र और पंडराबिस के परगना को छोड़कर, लेकिन निरमंड तहसील के जगत- खाना और बुरो गांव सहित संपूर्ण जिला]</p>	<p>4000</p> <p>2400</p>	<p>5200</p> <p>3000</p>
	<p>(4) लाहौल और स्पीति जिला:</p> <p>लाहौल एवं स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र</p>	<p>4000</p>	<p>5200</p>
	<p>(5) शिमला जिला:</p> <p>(i) रामपुर तहसील में कूट , लबाना-सदाना , सरपारा और चाडी-ब्रांडा की पंचायतों का 15/20 क्षेत्र.</p> <p>(ii) डोरा कवर तहसील, रामपुर में दरकाली की ग्राम पंचायत , काशापठ तहसील और मुनीश, सरहन परगना का घोरीचाइबीस.</p> <p>(iii) सरहन परगना के चौपाल तहसील तथा घोरीस, पंजगाँव, पट्सनऊ, नौबीस और तीनकोटि, तकलेश क्षेत्र का देओती ग्राम पंचायत, रामपुर तहसील के रामपुर परगना का परगना बरबीस, कस्बा रामपुर और घोरी नोग, शिमला शहर और उसके उपनगर(ढल्ली, जतोग, कसूम्टी), मशोबरा, तारादेवी और तुतू.</p>	<p>4000</p> <p>3200</p> <p>2400</p>	<p>5200</p> <p>4200</p> <p>3000</p>
	<p>(6) कांगड़ा जिला:</p> <p>(i) बड़ा भांगल और छोटा भांगल के क्षेत्र</p> <p>(ii) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर और नगरनिगम सीमा के बाहर स्थित धर्मशाला में निम्नलिखित कार्यालय -महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), दारी, यांत्रिक कार्यशाला, रामनगर , बाल कल्याण और नगर एवं ग्राम योजना कार्यालयों, सकोह , निचले सकोह में सीआरएसएफ कार्यालय , कांगड़ा दूध आपूर्ति योजना,</p>	<p>3200</p>	<p>4200</p>

	<p>डुगियार , हिमाचल पथ परिवहन निगम (एच RTसी) कार्यशाला, सधेर, क्षेत्रीय मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्टरी, दारी, सिंचाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य (आईपीएच) उप-मंडल, दान, बंदोबस्ती कार्यालय, शामनगर, हिंवा परियोजना, शामनगर शामिल है.</p> <p>पालमपुर में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय (एचपीकेवीवी) परिसर सहित कांग्रा पालमपुर टाऊन जिला का और इसकी नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित लेकिन पालमपुर शहर में शामिल निम्नलिखित कार्यालय शामिल हैं – हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय परिसर, मवेशी विकास कार्यालय / जर्सी फार्म, बनूरी, रेशम उत्पादन कार्यालय / इंडो-जर्मन कृषि कार्यशाला या हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एचपीपीडब्ल्यूडी) डिवीजन, बुंदला, विद्युत उप- मंडल, लोहना, डीपीओ निगम, बुंदला , विद्युत एचईएसईई विभाग, घुग्गर.</p>	2400	3000
	<p>(7) मंडी जिला:</p> <p>जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी, बागडा की थूंग तहसील में पंचायत, छतरी, छोटधर, गरागुशैन, गटू, गरियास, जंजैहली, जरयार, जोहार, कलहाणी, कलवन , खोलानाल, लोथ, सिलीबागी, सोमचान, थचधार, ताची, थाना, धरमपुर ब्लॉक- बिंगा पंचायत, कमला, सकलाना, तन्यर और तरखोला, करसोग तहसील – बलीधार के तहसील , बागरा , गोपालपुर, खाजोल, महोग, मेहुदी, माँज, पेखी , साइज, सराहन और टेबन, सुंदरनगर तहसील - बोही के पंचायत, बटवारा, धन्यारा , पौरा - कोठी, सेरी और शोजा .</p>	2400	3000
	<p>(8) सिरमौर जिला:</p> <p>पंचायत बानी, बाखली (पच्छाद तहसील), भरोग भनेरी (पांवटा तहसील), बिरला (नाहन तहसील), डिब्बर (पच्छाद तहसील) और थानाकसोगा (नाहन तहसील) और थांसगिरि भूभाग</p>	2400	3000
	<p>(9) सोलन जिला :</p> <p>मंगल पंचायत.</p>	2400	3000
	<p>(10) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपर्युक्त (1) से (9) में सम्मिलित नहीं हैं.</p>	640	800
13.	<p>उत्तराखंड:</p> <p>चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र</p>	4000	5200
14.	<p>पश्चिम बंगाल</p> <p>दक्षिण 24 परगना जिला</p> <p>सुंदरबन क्षेत्र (डैम्पियर हॉज की रेखा से दक्षिण), अर्थात्, भानातुश खाली (रामपुरा), कुमिरमारी (बगना), झिंगाखली , सजनाखली , गोसाबा ,</p>	1000	1000

अमलामाथी (बिद्या), कैनिंग, कुलतली, पियाली, नालगढा, रायदिघी, भांची, पाथरप्रतिमा, भागवतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, शिकारपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुमारी, कुलटोला, घुशियोघाटा (कुल्टी)		
---	--	--

विवरणात्मक ज्ञापन

यह विनियम जो पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए गए हैं, वे भारतीय बैंक संघ द्वारा सदस्य बैंकों की ओर से इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश तथा बैंकों के शीर्ष स्तरीय अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोटों की सहमत शर्तों के अनुसार हैं. इसलिए, ऐसे पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

सी. एम. मिनोचा, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./708/2024-25]

नोट : संशोधित विनियम भारत के राजपत्र, भाग III खंड 4 में प्रकाशित किये गए. निम्नलिखित अधिसूचनाओं का संदर्भ ले, यथा :-

क्रम सं.	राजपत्र अधिसूचना सं.	आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	ओएसआर/1	14.11.1987
2.	ओएसआर/2	04.06.1988
3.	ओएसआर/3	04.06.1988
4.	ओएसआर/4	30.12.1989
5.	ओएसआर/5	27.10.1990
6.	ओएसआर/6	11.01.1992
7.	ओएसआर/7	12.12.1992
8.	ओएसआर/8	27.02.1993
9.	ओएसआर/9	25.09.1993
10.	ओएसआर/10	10.09.1994
11.	ओएसआर/11	07.01.1995
12.	ओएसआर/12	07.09.1996
13.	ओएसआर/13	21.12.1996
14.	ओएसआर/14	21.12.1996
15.	ओएसआर/15	21.12.1996
16.	ओएसआर/15	06.02.1996
17.	ओएसआर/16	03.06.2000
18.	ओएसआर/16	30.12.2000
19.	ओएसआर/17	09.12.2000
20.	ओएसआर/18	29.10.2002
21.	ओएसआर/19	18.06.2003
22.	ओएसआर/20	27.01.2006
23.	ओएसआर/21	10.03.2007
24.	ओएसआर/22	25.09.2017
25.	ओएसआर/23	31.03.2020

UNION BANK OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 27th November, 2024

No. CO:ERD:PD:798:2024.—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Union Bank of India, in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services letter No. 4/2/2/2015-IR, dated the 18th December, 2020, on and from the 1st November, 2017 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the Union Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Union Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Union Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, -

(1) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

“(f) “family” for the purposes of medical facilities and for the purpose of leave fare concession means, the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children) wholly dependent physically and mentally challenged brother or sister with forty percent or more disability, widowed daughters and dependent divorced / separated daughters, sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters and parents wholly dependent on the officer.

Explanation.—

- (i) The expression “wholly dependent family member” shall mean such member of the family having an income not exceeding ₹12,000/- per month. If the income of one of the parents exceeds ₹12,000/- per month or the aggregate income of both the parents exceeds ₹12,000/- per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.
- (ii) A married female officer may include her natural parents or parents-in-law under the definition of family, but not both, provided that the parents or parents-in-law are wholly dependent on her.

Note: (1) For the purpose of medical expenses reimbursement scheme, for all officers, i.e., male or female, any two of the dependent parents or parents-in-law shall be covered. The officer will have the choice to substitute either of the dependents or both.

Note: (2) Physically challenged children of an officer to be defined as dependents irrespective of age or marital status, subject to income criteria;”.

(2) for clause (i) of the said regulations, the following clause shall be substituted namely: —

“Managing Director” means the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank;

3. In regulation 4 of the said regulations, —

- (i) in sub-regulation (6), the *Explanation* shall be omitted;
- (ii) for sub-regulations (7), (8) and (9), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(7) With effect from the 1st November, 2017, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

(a) Top Executive Grade

Scale VII = ₹116120 – 3220/4 – 129000

Scale VI = ₹104240 – 2970/4 – 116120

(b) Senior Management Grade

Scale V = ₹ 89890 – 2500/2 – 94890 – 2730/2 – 100350

Scale IV = ₹ 76010 – 2220/4 – 84890 – 2500/2 – 89890

(c) Middle Management Grade

Scale III = ₹ 63840-1990/5– 73790 - 2220/2 - 78230

Scale II = ₹ 48170-1740/1 - 49910 -1990/10 - 69810

(d) Junior Management Grade

Scale I = ₹ 36000-1490/7- 46430-1740/2-49910-1990/7-63840.

Explanation.— Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on the 31st October, 2017 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on the 1st November, 2017 on stage-to-stage basis, i.e., on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(8) With effect from 31st March, 2020, the scales of pay specified for Top Executive Grade Scale – VIII shall be as under: –

Scale VIII = Rs 166350-4400/4 - 183950

(9) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(iii) after sub-regulation (9) the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

(10) (a) With effect from the 1st November, 2012, officers shall be paid special allowances as under: –

Scale I – III - 7.75 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 10% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI – VII - 11 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(b) With effect from the 1st November, 2017, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – III - 16.40 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 19 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI - VIII - 20 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon:

Provided that an officer in Scale VIII will be eligible for special allowance with effect from 31st March, 2020.

Note: The special allowance referred to in clauses (a) and (b) of sub-regulation 10 with applicable dearness allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including New Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.”.

4. In regulation 5 of the said regulations, –

(i) For sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: –

“(1) Subject to the provisions of sub-regulations (7) and (8) of regulation 4, on and from the 1st November, 2017, the increments shall be granted subject to the following, namely: –

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulations (7) and (8) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) one year after reaching maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher Scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar;
- (c) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for middle management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher Scale, shall be eligible for five stagnation increments for every two completed years of service of which the first two shall be Rs. 1990/- each and the next three of Rs 2220/- each:

Provided that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment two years after release of the fourth stagnation increment or on the 1st of November 2017, whichever is later;

- (d) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b), after reaching maximum of higher Scale, shall be eligible for five stagnation increments of Rs. 2220/- each for every two completed years of service:

Provided that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment two years after release of the fourth stagnation increment or on the 1st November, 2017, whichever is later;

- (e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III i.e., those who are recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III shall be eligible for six stagnation increments out of which first four stagnation increments of Rs. 2220/- each will be granted for every two years of completed service after reaching the maximum and the next two stagnation increments of Rs. 2500/- each shall be granted for every two years of completed service after receiving the fourth stagnation increment:

Provided that the sixth stagnation increment shall be released two years after release of fifth stagnation increment or on the 1st November, 2017, whichever is later;

- (f) officers in Senior Management Grade Scale IV shall be eligible for two stagnation increments after reaching the maximum of scale, for every two completed years of service, of which first stagnation increment shall be of Rs. 2500/- and the second stagnation increment shall be of Rs. 2730/-:

Provided that the officer shall be eligible for the second stagnation increment two years after release of first stagnation increment or on the 1st of November 2017, whichever is later;

- (g) the stagnation increments received by the officers from Scale I to Scale IV during their service in bank as on the 1st November, 2017 as per periodicity herein before would be readjusted from three years periodicity to two years periodicity from the date of reaching their maximum and officer shall be notionally eligible for stagnation increments w.e.f the 1st November, 2017 as per the revised periodicity which will qualify for superannuation benefits. However, monetary benefit on account of such revised and readjusted periodicity of stagnation increments shall be payable from the 1st November, 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later;

- (h) officer in Senior Management Grade Scale V shall be eligible for one stagnation increment of Rs 2970/- two years after reaching the maximum scale of pay or on the 1st of November 2020, whichever is later:

Provided that such increments shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation. - Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.”;

- (ii) in sub-regulation (2), in the *Explanation*, after clause (g) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely: -

“(h) on and from the 1st November, 2017, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers Part I	(i) Rs. 1020 per month one year after reaching maximum of the scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs. 1020 per month one year after reaching maximum of the Scale. (ii) Rs. 2550 per month two years after reaching maximum of the Scale:

Provided that an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification, the first installment of professional qualification pay and the release of subsequent installments of professional qualification pay shall be with reference to the date of release of the first installment of such professional qualification pay.”;

- (iii) in sub-regulation (3), -

- (a) in clause (f), after the Table, Notes (i) to (vi) shall be omitted;
(b) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

“(g) on and from the 1st of November, 2017, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service: -

TABLE

Sl. No.	Increment component (Rs.)	Dearness Allowance as on the 1 st November, 2017 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
1.	(1)	(2)	(3)
2.	1990	53	2043
3.	2220	59	2279
4.	2500	66	2566
5.	2730	73	2803
6.	2970	79	3049
7.	3220	86	3306

Note:

- (i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the Tables in clauses (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of this sub-regulation shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.
- (ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the aforesaid Table and House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4), (5) (6) and (7) of regulation 4 is earned.
- (iii) Only officers who are in the service of the Bank on or before the 1st November, 1993 will be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay they are placed.
- (iv) On and from the 1st of November, 1999, there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of professional qualification pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after the 1st of November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of professional qualification pay, if any, shall be released on the 1st of November, 2000.

- (v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.
- (vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e) and (f) above, one year after reaching the maximum of the scale:
- (h) On and from the 31st March, 2020, other things being equal, the Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade Scale – VIII shall be at the rates given in the Table below and shall remain frozen for the entire period of service:

TABLE

Increment component (Rs.)	Dearness Allowance on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
4400	117	4517"

5. In regulation 20 of the said regulations, in sub-regulation (1), in clause (c), the words "Chairman &" shall be omitted.

6. In regulation 21 of the said regulations,—

- (a) in sub-regulations (6), in the *Explanation*, in clause (b), for the brackets, word and letters "(f) and (g)", the brackets, word and letters "(f), (g) and (h)" shall be substituted;
- (b) after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

- “(7) On and from the 1st day of November, 2017, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.07% of Pay.”;

7. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1) On and from the 1st November, 2017,—

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.50 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) Where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Place of work	House Rent Allowance
1.	(2)	(3)
2.	Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	9.0% of Pay
3.	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	8.0% of Pay
4.	Other places	7.0% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.50 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) of the above Table.

Note: The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent. of House Rent Allowance as hitherto.”.

8. In regulation 23 of the said regulations,—

- (A) For sub-regulations (i), (ii), (iii), (iv) and (v), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely: —

- “(i) On and from the 1st November, 2017, if an officer is serving in a place mentioned in column (1) of the Table below, a city compensatory allowance at the rate mentioned in column (2) thereof against that place shall be payable:

TABLE

Sl. No.	Places	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Places in Area I and above and in the State of Goa	Rs. 1400/- per month
2.	Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Rs. 1150/- per month

- (ii) On and from the 1st November, 2017, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations.
- (iii) On and from the 1st November, 2017, if an officer is serving in an area specified as Project Area falling in Group A or Group B, he/she shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of

Rs.600/- per month or Rs.525/- per month according to the classification of area as Group A or Group B respectively.

- (iv) On and from the 1st November, 2020, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he/she has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs. 1650/- per month from the date he/she reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.
- (v) On and from the 1st November, 2020, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he/she may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent. of pay subject to a maximum of Rs. 6000/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he/she is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he/she shall receive a deputation allowance equal to four per cent. of his/her pay subject to a maximum of Rs. 3000/- per month:

Provided further that an officer on deputation to the training establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent. of his/her pay subject to a maximum of Rs. 3000 per month.”;

(B) for sub-regulation (viii), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(viii) On and from the 1st November, 2017, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs. 300 per month.”;

(C) for sub-regulation (x), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

“(x) On and from 1st November, 2017, an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the Table below, namely:—

TABLE

Sl No.	Place	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.1125/- per month
2.	Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.1500/- per month
3.	Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.3000/- per month”;

(D) after sub-regulation (x), the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

“(xi) On and from the 1st of November, 2017, an Officer shall be eligible for learning allowance of Rs. 600/- per month along with Dearness Allowance thereon.

(xii) On and from the 1st November, 2017, an officer shall be eligible for a fixed allowance of Rs.700/- per month who are posted in areas other than the areas that are eligible for City Compensatory Allowance.

This fixed allowance shall not be reckoned for payment of Dearness Allowance, superannuation benefits, viz, pension including New Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.

- (xiii) From the financial year 2020-21, Performance Linked Incentive shall be payable to all officers annually based on Operating Profit or Net Profit over and above the normal salary payable. The Performance Linked Incentive matrix mentioned below shall decide the amount payable (in number of days of pay = Basic + Dearness Allowance) depending on the annual performance of the Bank:

Sl. No.	Year on year growth in operating Profit	Number of days for which salary (Basic + Dearness Allowance) shall be paid
(1)	(2)	(3)
1.	< 5%	Nil
2.	5% to 10%	5 days
3.	> 10% to 15%	10 days*
4.	> 15%	15 days*

*3rd and 4th slabs are payable only if the Bank has Net Profit. If a Bank has growth in operating profit of 5 percent and more, but there is no Net Profit, then minimum 2nd slab of 5 days shall be payable.”.

9. In regulation 24 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1) On and from the 1st November, 2017, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the Table below, namely: -

TABLE

Sl. No.	Grade	Maximum limit of reimbursement
(1)	(2)	(3)
1.	Junior Management and Middle Management Grade	Rs.10300/- per annum or the amount incurred whichever is less
2.	Senior Management and Top Executive Grade	Rs.12300/- per annum or the amount incurred whichever is less

Note: (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above; or

(ii) for the year 2017, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November, 2017 and December, 2017.”.

10. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st November, 2017, a sum equal to 0.50 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he/she is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.10 per cent. of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he/she is placed shall be recovered by the Bank from him/her:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

11. In regulation 32 of the said regulations, in sub-regulation (2), after the proviso, the following Explanation shall be inserted namely:-
- “Explanation. - For the purpose of this regulation, it is clarified that –
- (a) casual leave not availed in the year 2017 or any subsequent years shall lapse in the following five year:
- (b) on and from the 1st of November, 2020, the unavailed casual leave by the officer shall be permitted on medical grounds and no medical certificate is required for the period of such un availed casual leave at a stretch not exceeding four days.”.
12. In regulation 33 of the said regulations,—
- (a) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -
- “(4) On and from the 1st June, 2015, privilege leave may be accumulated upto not more than two hundred seventy days except where leave has been applied and it has been refused:
- Provided that encashment of privilege leave shall be restricted upto a maximum of two hundred forty days:
- Provided further that from the calendar year, 2020, an officer shall also be eligible for encashment of privilege leave at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of his choice and an officer who have already completed fifty five years of age as on 1st January, 2020 and above shall be eligible to encash privilege leave at the rate of seven days for each calendar year till his retirement as a one-time measure.”;
- (b) for sub-regulation (5) the following sub-regulation shall be substituted, namely:—
- “(5) An officer desiring to avail of privilege leave shall ordinarily give not less than ten days notice of his intention of avail of such leave except for the purpose of leave fare concession.
- (c) after sub-regulation (5), following sub-regulation shall be inserted, namely:-
- “(6) Privilege leave taken on sick grounds, when there is no credit in the sick leave account of the officer, shall not be counted as an occasion of availing privilege leave.”.
13. In regulation 34 of the said regulations, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—
- “(5) Women officers may avail sick leave for the sickness of their children of eight years and below subject to production of medical certificate.”.
14. For regulation 35 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—
- “35. Additional Sick Leave.- (1) On and from the 1st January, 1989, where an officer has put in a service of twenty four years, he/she shall be eligible to additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of twenty four years subject to a maximum of three months of additional sick leave.
- (2) On and from the 1st November, 2017, where an Officer has put in a service of thirty years, he/she shall be eligible for further additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of thirty years subject to a maximum of three months of additional sick leave:
- Provided that the total number of sick leaves shall not exceed seven hundred and twenty days in the entire service of the officer:
- Provided further that in case of additional sick leaves availed on or after the 29th June, 1999, commutation of additional leave may be allowed in accordance with sub-regulation (2) of regulation 34.”.
15. For regulation 36 of the said regulations, the following sub-regulations shall be substituted, namely:—
- “36 Maternity Leave.- (1) In case of maternity leave,—
- (a) a female employee shall be eligible for maternity leave on substantive pay for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:
- Provided that in case of delivery of twins, the period of maternity leave shall be eight months:
- Provided further that maternity leave may be availed combining with any other kind of leave except casual leave;
- (b) in case of miscarriage, medical termination of pregnancy or abortion, female employee may avail maternity leave upto six weeks on the basis of medical certificate or advice of a competent medical

practitioner, i.e., a qualified gynecologist. In special or exceptional cases involving medical complications, associated with miscarriage or medical termination of pregnancy or abortion, maternity leave may be availed beyond six weeks, if advised by a competent medical practitioner (qualified gynaecologist) but upto six months only on any one occasion, within the overall limit of twelve months during the entire period of service;

- (c) within the overall period of twelve months, leave may also be availed in case of hysterectomy upto a maximum of sixty days.

Note: In the case of employees who have availed and exhausted maternity leave of twelve months, leave of fifteen days shall be sanctioned over and above the same, subject to production of medical certificate;

- (d) a childless female employee may avail leave once during service for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely: –

- (i) leave will be granted for adoption of only one child;
- (ii) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;
- (iii) the permanent part-time employees are also eligible for grant of leave for adoption of a child;
- (iv) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;
- (v) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service;

- (e) within the overall period of twelve months, leave may also be availed in case of hospitalisation on account of the following gynecological ailments or treatments up to a maximum of thirty days, namely :–

- (i.) Abnormal Uterine Bleeding (AUB);
- (ii.) Ovarian Tumor;
- (iii.) Tubectomy or Tubectomy reversal;
- (iv.) Post-Partum Depression (PPD);
- (v.) Post-Partum Hemorrhage (PPH);
- (vi.) Acute Pelvic Inflammatory Disease (Acute PID);
- (vii.) Dysfunction Uterine Bleeding; Dysfunction (DUB).

- (2.) In case of paternity Leave, with effect from the 1st June 2015, a male employee with up to two surviving children shall be eligible for fifteen days Paternity leave during his wife's confinement and this leave may be combined with any other kind of leave except casual leave:

Provided that the leave may be availed up to fifteen days before or upto six months from the date of delivery of the child:

Provided further that paternity leave as above shall be allowed to a male employee with up to two surviving children for legally adopting a child who is below one year of age.”.

16. For regulation 37 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:–

“37. Extra-ordinary leave.– (1) An officer shall be eligible for extraordinary leave on loss of pay for not more than twenty four months during the entire period of service.

- (2) An officer may avail extraordinary leave on any one occasion for a period not exceeding three months and in extreme medical circumstances, he/she may avail extraordinary leave up to four months on any one occasion.

Note : The employee will not be losing any seniority on account of availing extraordinary leave on medical grounds.”.

17. For regulations 37A in the said regulation, following regulations may be substituted, namely: –

“37A. Special casual leave and special leave.— (1) With effect from the 1st November, 2020, an officer employee shall be eligible for special casual leave on occasions when the branch where the officer is working or the place where he/she is residing is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods, etc.

(2) With effect from the 1st of November, 2020, a physically or orthopedically handicapped officer shall be eligible for four days’ special casual leave.

(3) An officer may also be granted special casual leave and any special leave as may be decided by the Board in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time.”

18. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) Halting allowance - On and from the 1st November, 2020, an officer in the grades or scales set out in column (1) of the Table shall be entitled to ‘per diem’ halting allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely: -

TABLE

Sl. No.	Grades/Scales of officers	Metro Rs.	Major ‘A’ Class cities Rs.	Area I Rs.	Other Places Rs.
1.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Officers in Scale VI and above	2700	1950	1650	1425
3.	Officers in Scale IV and V	2250	1950	1650	1425
4.	Officers in Scale I, II and III	1950	1650	1425	1200:

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, halting allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation .— For the purpose of computing halting allowance “per diem” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours.”.

19. In regulation 42 of the said regulations, for clause (c) of sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely: –

“(3) (c) On and from the 1st November, 2020 an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely: -

TABLE

Sl. No.	Grade/Scale	Amount
1.	(1)	(2)
2.	Top Executive and Senior Management (Officers in Scale IV and above)	Rs.30,000/-
3.	Middle Management and Junior Management (Officers upto Scale III)	Rs. 25,000/-.”.

20. In regulation 45 of the said regulations, before the note to sub-regulation (4), the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that with regard to officers covered under Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), the Bank shall make a contribution of fourteen percent of pay plus dearness allowance with effect from the 11th November, 2020:

Provided further that the service charges of the Service Provider or Fund Manager of New Pension Scheme shall be borne by the Bank from the financial year 2020-21.”.

21. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely: -

“Schedule

(see sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st November, 2017, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely: -

Special Area Allowance

Sl. No.	AREA	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.36,001/-	Pay above Rs.36,001/-
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mizoram (a) Chimpui district and areas beyond 25 kilometres from lunglei town in Lunglei district.	4000	5200
	(b) entire Lunglei district excluding areas beyond 25 kilometres from Lunglei town.	3200	4200
	(c) entire Aizawl district	2400	3000
2.	Nagaland	3200	4200
3.	Andaman and Nicobar Islands (a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands (b) South Andaman (including Port Blair)	4000 3200	5200 4200
4.	Sikkim	4000	5200
5.	Lakshadweep Islands	4000	5200
6.	Assam	640	800
7.	Meghalaya	640	800
8.	Tripura (a) difficult areas of Tripura	3200	4200
	(b) throughout Tripura except difficult areas.	2400	3000
9.	Manipur	2400	3000
10.	Arunachal Pradesh (a) difficult areas of Arunachal Pradesh (b) throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	4000 3200	5200 4200
11.	Jammu and Kashmir (a) Kathua district: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	4000	5200
	(b) Udhampur district: (i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamagillaqa, other than those included in Part 2(b). (ii) Areas up to Goel from Kamban side and areas upto Arnas from Keasi side in tehsil Mohre.	4000 3200	5200 4200
	(c) Doda district: Illaquas of Padder and NiabatNowgam in Kishtwar tehsil	4000	5200

	(d) Leh district : all places in the district	4000	5200
	(e) Barmulla district: (i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar sub-division and KeranIllaqua (ii) Matchill	4000 3200	5200 4200
	(f) Poonch and Rajouri district : areas in Poonch and Rajouri district excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two districts	2400	3000
	(g) Areas not included in (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the state government for their own staff.	2400	3000
12.	Himachal Pradesh		
	(1) Chamba district (a) Pangi tehsil, Bharmour tehsil, panchayats:Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata (b) Bharmour tehsil, excluding panchayats and villages included in (a) above. (c) Jhandru panchayat in Bhatiyat tehsil,Churah tehsil, Dalhousie town (including Banikhet proper).	4000 3200 2400	5200 4200 3000
	(2) Kinnaur district: (i) Asrang, Chitkul and HangoKuno/ Charang panchayats, 15/ 20 Area comprising the gram panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh sub-division, excluding the panchayat areas specified above. (ii) entire district other than areas included in (a) above.	4000 3200	5200 4200
	(3) Kullu district: (i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga (ii) [Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand tehsil) and entire district excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of tehsil Nirmand]	4000 2400	5200 3000
	(4) Lahaul and Spiti district: entire area of Lahaul and Spiti	4000	5200
	(5) Shimla district: (i) 15/20 area of Rampur tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda. (ii) Dora-Kawar tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath tehsil and Munish, Ghorichaibis of Pargana Sarahan. (iii) Chopal tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghor Nog of Pargana Rampur of Rampur tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	4000 3200 2400	5200 4200 3000
	(6) Kangra district: (i) Areas of Bara Bhagal and Chhota Bhagal	3200	4200

	<p>(ii) Dharamshala Town of Kangra district and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala town-Women's Industrial Training Institute (ITI), Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, Himachal Road Transport Corporation (HRTC) Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, Irrigation and Public Health (I.P.H.) Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar.</p> <p>Palampur Town of Kangra District including Himachal Pradesh Krishi Vishwa Vidyalaya (HPKVV) Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop or Himachal Pradesh Public Works Department (HPPWD) Division, Bundla, Electrical sub-division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE division, Ghuggar.</p>	2400	3000
	<p>(7) Mandi district:</p> <p>Chhuahar Valley of Jogindernagar tehsil, panchayats in thunag tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, panchayats of Dharampur block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, panchayats of Karsog tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, panchayats of Sundernagar tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.</p>	2400	3000
	<p>(8) Sirmaur District:</p> <p>panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad tehsil), Bharog Bheneri (Paonta tehsil), Birla (Nahan tehsil), Dibber (Pachhad tehsil) and ThanaKasoga (Nahan tehsil) and Thansgiri Tract</p>	2400	3000
	<p>(9) Solan district :</p> <p>Mangal Panchayat.</p>	2400	3000
	<p>(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.</p>	640	800
13.	<p>Uttarakhand:</p> <p>Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat districts</p>	4000	5200
14.	<p>West Bengal South 24 Pargana District</p> <p>Sunderban Areas (south of Dampier Hodge's line), namely, Bhanatush Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhingakhali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, PatharPratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingalganj, Basanti, kuemari, Kultola, Ghushioghata (Kulti)</p>	1000	1000

EXPLANATORY MEMORANDUM

These Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific

mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

C M MINOCHA, Chief General Manager
[ADVT.-III/4/Ext./708/2024-25]

Note: The amendment regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 vide following notifications, namely:-

Sl. No.	Gazette Notification No	Date of publication in the Official Gazette
1.	OSR/1	14.11.1987
2.	OSR/2	04.06.1988
3.	OSR/3	04.06.1988
4.	OSR/4	30.12.1989
5.	OSR/5	27.10.1990
6.	OSR/6	11.01.1992
7.	OSR/7	12.12.1992
8.	OSR/8	27.02.1993
9.	OSR/9	25.09.1993
10.	OSR/10	10.09.1994
11.	OSR/11	07.01.1995
12.	OSR/12	07.09.1996
13.	OSR/13	21.12.1996
14.	OSR/14	21.12.1996
15.	OSR/15	21.12.1996
16.	OSR/15	06.02.1996
17.	OSR/16	03.06.2000
18.	OSR/16	30.12.2000
19.	OSR/17	09.12.2000
20.	OSR/18	29.10.2002
21.	OSR/19	18.06.2003
22.	OSR/20	27.01.2006
23.	OSR/21	10.03.2007
24.	OSR/22	25.09.2017
25.	OSR/23	31.03.2020